भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3318

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है

केंद्र और राज्य सरकारों के विरूद्ध दर्ज किए गए मामले

3318 श्री बिनोय विस्वमः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत वर्षों के दौरान केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के विरूद्ध दर्ज किए गए मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2017 से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विरूद्ध दाखिल किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ;

(घ) ऐसे मामलों के लिए वाद करने के लिए उत्तरदायी सरकारी वकीलों (जीपी), लोक अभियोजकों (पीपी) तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों के पदों की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ङ) ऐसे मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : उपलब्ध आंकड़ा के अनुसार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा और उनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में फाइल किए गए औसतन मामलों की संख्या में कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, लेकिन कई गुना नहीं।

(ख) और (ग) : जानकारी भारत के उच्चतम उच्च न्यायालय और 14 उच्च न्यायालयों के लिए उपलब्ध है, जो **उपाबंध** के अनुसार दी गई है।

(घ) : जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों का संबंध है वें मामलें में बहस नहीं करते है किन्तु उनका न्यायनिर्णय करते है । इसके अतिरिक्त, उनके चयन और नियुक्ति का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों की होती है, जो संबंधित राज्य न्यायिक सेवा नियमों में यथा परिकल्पित भर्ती/प्रोन्नति के माध्यम से की जाती है । जहां तक सरकारी अधिवक्ताओं/लोक अभियोजकों की रिक्तियों का संबंध है, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित होने पर भर्ती के माध्यम से भरा जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार भारत संघ के मुक्कदमों से संबंधित मामलों में अभिवचन/प्रतिवाद के लिए सरकारी वकीलों को नियुक्त करती है। 30.03.2022 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगे पैनल परामर्शियों की संख्या **उपाबंध-2** पर है । इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार अपेक्षित होने पर गृह मंत्रालय, सीबीआई, राजस्व विभाग आदि के मामलों के संचालन के लिए लोक अभियोजकों/विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करती है।

(ङ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक बुनियादी ढांचे, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण,साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं।

****

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3318 तारीख 31 मार्च, 2022 के लिए उपाबंध

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>न्यायालय का नाम</th><th>(ख) यदि हां, 2017 से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विरुद्ध फाइल किए गए और निपटाए गए राज्य और वर्ष वार मामलों के ब्यौरे, ;</th><th>(ग) पांच वर्ष से अधिक लंबित ऐसे मामलों की संख्या ;</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भारत का उच्चतम न्यायालय</td><td>इस प्रकार मांगी गई रीति में जानकारी का रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, 'केंद्रीय सरकार' के लिए खोजे गए पाठ को छोड़कर "केंद्रीय सरकार" जैसे 'यूओआई', 'यू.ओ.आई', 'यूनियन ऑफ इंडिया', 'भा.सरकार' 'भा.सरकार', और 'राज्य सरकार' जैसे 'सरका.', 'सरका.', 'सरकार' और 'राज्य' के लिए पार्टी के नाम से अंतर्विष्ट खोजे गए पाठ के आधार पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध फाइल किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या 2017 से, भारत के उच्चतम न्यायालय में 26.03.2022 को एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त किए गए वर्ष-वार और राज्य-वार,अनुसार निम्नानुसार है:
केंद्रीय सरकार
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">याचिकाकर्ता के रूप में</th><th colspan="2">प्रत्यर्थी के रूप में</th></tr>
<tr><th>फाइल किए गए</th><th>निपटाए गए</th><th>फाइल किए गए</th><th>निपटाए गए</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>708</td><td>582</td><td>3690</td><td>2958</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>742</td><td>539</td><td>3985</td><td>3177</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>826</td><td>486</td><td>4249</td><td>2970</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>790</td><td>376</td><td>3544</td><td>2058</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>879</td><td>306</td><td>2882</td><td>1497</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>196</td><td>14</td><td>691</td><td>155</td></tr>
</table>
<u>राज्य सरकार</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">याचिकाकर्ता के रूप में</th><th colspan="2">प्रत्यर्थी के रूप में</th></tr>
<tr><th>फाइल किए गए</th><th>निपटाए गए</th><th>फाइल किए गए</th><th>निपटाए गए</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>3836</td><td>2974</td><td>17849</td><td>15679</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>3667</td><td>2662</td><td>20830</td><td>17706</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>3862</td><td>2259</td><td>18874</td><td>14731</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2722</td><td>1445</td><td>12272</td><td>8769</td></tr>
</table>
</td><td>26.03.2022 को एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त भारत के उच्चतम न्यायालय में 2017 से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार है:
<table>
<tr><td>याचिकाकर्ता के रूप में केंद्रीय सरकार</td><td>1807</td></tr>
<tr><td>प्रत्यर्थी के रूप में केंद्रीय सरकार</td><td>6104</td></tr>
<tr><td>याचिकाकर्ता के रूप में राज्य सरकार</td><td>6426</td></tr>
<tr><td>प्रत्यर्थी के रूप में राज्य सरकार</td><td>20637</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2021</td><td>2391</td><td>1131</td><td>14518</td><td>9349</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>740</td><td>93</td><td>4254</td><td>1270</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>बाम्बे उच्च न्यायालय</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>फाइल किए गए</th><th>निपटाए गए</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>56609</td><td>45039</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>60841</td><td>41825</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>61692</td><td>41781</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>27803</td><td>15855</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>43280</td><td>23582</td></tr>
</table>
</td><td>45365 मामले</td></tr>
<tr><td>3</td><td>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">उच्च न्यायालय के लिए</th></tr>
<tr><th>फाइल किए गए मामले</th><th>निपटाए गए मामले</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>35307</td><td>31493</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>41333</td><td>37215</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>45230</td><td>39488</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>30198</td><td>23678</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>35974</td><td>30809</td></tr>
<tr><td>2022 (22.03.2022 तक)</td><td>10325</td><td>7008</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पण- उपर्युक्त आंकड़े कुल मामलों की संख्या हैं और अधिकांश मामले केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विरुद्ध हैं ।</td></tr>
</table>
</td><td>23986 मामले</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>गुवाहाटी उच्च न्यायालय</td>
<td>2017 से केंद्रीय सरकार के विरुद्ध फाइल किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या :
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>फाइल किए गए मामलों की सं0</th><th>निपटाए गए मामलों की सं0</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>3022</td><td>3479</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>4225</td><td>2677</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>5309</td><td>2839</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>2285</td><td>1237</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>2716</td><td>1624</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>725</td><td>419</td></tr>
</table>
</td>
<td>2017 से राज्य सरकार के विरुद्ध फाइल किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या :
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>फाइल किए गए मामलों की सं0</th><th>निपटाए गए मामलों की सं0</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>15444</td><td>20914</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>19422</td><td>17296</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>22276</td><td>19060</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>14557</td><td>12103</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>17693</td><td>14225</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>4319</td><td>3700</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>राज्य सरकार</td><td>5831</td></tr>
<tr><td>केंद्रीय सरकार</td><td>1314</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय</td>
<td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">संस्थित</th><th colspan="2">निपटान</th></tr>
<tr><th>राज्य सरकार</th><th>केंद्रीय सरकार</th><th>राज्य सरकार</th><th>केंद्रीय सरकार</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>105870</td><td>2123</td><td>94614</td><td>2842</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>105070</td><td>1910</td><td>89813</td><td>2587</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>107893</td><td>1958</td><td>89698</td><td>2481</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>87127</td><td>1409</td><td>68621</td><td>1346</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>111155</td><td>1906</td><td>92550</td><td>1778</td></tr>
<tr><td>2022 (फरवरी, 2022 तक)</td><td>20251</td><td>352</td><td>20574</td><td>494</td></tr>
</table>
</td>
<td>केंद्रीय सरकार - 6051 मामले

राज्य सरकार – 141231 मामले</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>6</td>
<td>उड़ीसा उच्च न्यायालय</td>
<td>2017 से लंबित और निपटाए गए मामले
<table>
<tr><th></th><th>लंबित मामले</th><th>निपटाए गए मामले</th></tr>
<tr><td>केंद्रीय सरकार</td><td>3558</td><td>4256</td></tr>
<tr><td>राज्य सरकार</td><td>16429</td><td>20596</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय</td>
<td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>फाइल किए गए</th><th>निपटाए गए</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>38133</td><td>32874</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>40859</td><td>32693</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>42922</td><td>38606</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>24218</td><td>17275</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>29944</td><td>17910</td></tr>
<tr><td>2022 (28.02.2022 तक)</td><td>4147</td><td>3235</td></tr>
</table>
</td>
<td>60898 मामले</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>पटना उच्च न्यायालय</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">उच्च न्यायालय में केंद्रीय सरकार के विरुद्ध मामलों के ब्यौरे</th><th colspan="2">उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध मामलों के ब्यौरे</th></tr>
<tr><th>वर्ष के दौरान फाइल किए गए/संस्थित मामलों की संख्या</th><th>वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या</th><th>वर्ष के दौरान फाइल किए गए/संस्थित मामलों की संख्या</th><th>वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>1427</td><td>1288</td><td>93235</td><td>89506</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>1484</td><td>1223</td><td>119004</td><td>108812</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>1571</td><td>1253</td><td>125887</td><td>110762</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>680</td><td>512</td><td>55273</td><td>43308</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>1695</td><td>666</td><td>100907</td><td>58636</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th>सरकार</th><th>पटना उच्च न्यायालय, पटना में केंद्रीय सरकार के विरुद्ध पांच वर्ष से अधिक लंबित मामले (23.03.2022 के अनुसार)</th></tr>
<tr><td>केंद्रीय सरकार</td><td>1621</td></tr>
<tr><td>राज्य सरकार</td><td>54716</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		2022 (23.03.2022तक)	403	273	20369	22821	

9	केरल उच्च न्यायालय	न्यायालय का नाम	वर्ष	केंद्रीय सरकार के विरुद्ध		राज्य सरकार के विरुद्ध		केंद्रीय सरकार – 11 राज्य सरकार – 2059 केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों के संबंध में, वर्तमान में लंबित मामलों की सही संख्या, जो कि 5 वर्षों की अवधि से लंबित हैं, उन रिपोर्टों का उपयोग करके निर्धारित नहीं की जा सकती हैं जो कर सकती हैं वर्तमान में सीएमएस से उत्पन्न किया जा सकता है और वर्तमान में केवल एक समय में लंबित मामलों की समग्रता निर्धारित की जा सकती है।
				फाइल किए गए	निपटाए गए	फाइल किए गए	निपटाए गए	
		केरल उच्च न्यायालय	2017	2880	1807	39111	35737	
			2018	4612	2970	43802	37405	
			2019	3573	3768	37711	36481	
			2020	3894	1960	29970	25316	
			2021	3625	2404	33388	27419	
			2022	1226	687	9682	6930	
10	मणिपुर उच्च न्यायालय	वर्ष	केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध फाइल किए गए मामलों की संख्या		निपटान किए गए मामलों की संख्या			17 मामले
		2017	17		7			
		2018	8		20			
		2019	14		6			
		2020	8		8			
		2021	17		25			
		2022 (28.02.2022तक)	0		3			
11	उत्तराखंड उच्च	वर्ष	फाइल किए गए	निपटाए				पांच वर्ष से अधिक के लिए उच्च न्यायालय में 7108 लंबित मामले

<table>
<tr>
<td></td>
<td>न्यायालय</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>गए</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>15393</td><td>22563</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>17780</td><td>17924</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>18798</td><td>20078</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>13571</td><td>10832</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>16386</td><td>10613</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>2799</td><td>1931</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>कर्नाटक उच्च न्यायालय</td>
<td>
राज्य सरकार के विरुद्ध फाइल किए गए मामलों
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>सरकार के विरुद्ध फाइल किए गए मामलों</th><th>सरकार के विरुद्ध निपटान किए गए मामलों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2017(जनवरी-दिसंबर)</td><td>37020</td><td>9642</td></tr>
<tr><td>2018(जनवरी-दिसंबर)</td><td>37807</td><td>8579</td></tr>
<tr><td>2019(जनवरी-दिसंबर)</td><td>39634</td><td>7775</td></tr>
<tr><td>2020(जनवरी-दिसंबर)</td><td>52952</td><td>3699</td></tr>
<tr><td>2021(जनवरी-दिसंबर)</td><td>62746</td><td>4886</td></tr>
</table>
केंद्रीय सरकार के विरुद्ध फाइल किए गए मामलों
<table>
<tr><th></th><th>सरकार के विरुद्ध फाइल किए गए मामलों की संख्या</th><th>सरकार के विरुद्ध निपटान किए गए मामलों की संख्या</th></tr>
<tr><td>2017(जनवरी-दिसंबर)</td><td>644</td><td>138</td></tr>
<tr><td>2018 जनवरी-दिसंबर</td><td>800</td><td>74</td></tr>
<tr><td>2019 जनवरी-दिसंबर</td><td>846</td><td>78</td></tr>
<tr><td>2020 (जनवरी-दिसंबर)</td><td>711</td><td>47</td></tr>
<tr><td>2021 (जनवरी-दिसंबर)</td><td>896</td><td>142</td></tr>
<tr><td>2022(28.02.2022 तक)</td><td>71</td><td>30</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>राज्य सरकार</td><td>7763</td></tr>
<tr><td>केंद्रीय सरकार</td><td>260</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>13</td>
<td>जम्मू-कश्मीर और जम्मू में लद्दाख उच्च न्यायालय</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">उच्च न्यायालय</th></tr>
<tr><th>वर्ष</th><th>संस्थित</th><th>निपटाए गए</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>11852</td><td>10737</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>8081</td><td>9007</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>4969</td><td>4617</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>282</td><td>13950</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>451</td><td>11043</td></tr>
</table>
</td>
<td>उच्च न्यायालय में13003 मामले</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>गुजरात उच्च न्यायालय</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="3">उच्च न्यायालय</th></tr>
<tr><th>वर्ष</th><th>फाइल किए गए</th><th>निपटाए गए</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>43869</td><td>37782</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>51151</td><td>44086</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>53951</td><td>48585</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>42386</td><td>34283</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>51979</td><td>45120</td></tr>
<tr><td>2022 (28.03.2022 तक)</td><td>14144</td><td>11740</td></tr>
</table>
</td>
<td>17,726 मामले</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>मेघालय उच्च न्यायलय</td>
<td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>फाइल किए गए</th><th>निपटाए गए</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>626</td><td>602</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>793</td><td>720</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>833</td><td>692</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>551</td><td>357</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>557</td><td>285</td></tr>
<tr><td>2022 (28.02.2022 तक)</td><td>61</td><td>24</td></tr>
</table>
</td>
<td>5 मामलें</td>
</tr>
</table>

उपाबंध-2

30.03.2022 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में पैनल परामर्शी की संख्या

भारत का उच्चतम न्यायालय		समूह 'क' पैनल परामर्शी : 358 समूह 'ख' पैनल परामर्शी : 270 समूह 'ग' पैनल परामर्शी : 195 कुल : **823**
क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम (सभी न्यायपीठों सहित)	लगे हुए पैनल परामर्शी (लगभग आंकड़े)
1.	दिल्ली उच्च न्यायालय	471
2.	बॉम्बे उच्च न्यायालय	230
3.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	278
4.	मद्रास उच्च न्यायालय	192
5.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	155
6.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	341
7.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	01
8.	मणिपुर उच्च न्यायालय	06
9.	मेघालय उच्च न्यायालय	02
10.	सिक्किम उच्च न्यायालय	01
11.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	00
12.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	36
13.	तेलंगाना राज्य लिए उच्च न्यायालय	70
14.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	05
15.	जम्मू - कश्मीर में जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय	06
16.	झारखंड उच्च न्यायालय	05
17.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	04
18.	पटना उच्च न्यायालय	46
19.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	37
20.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	10
21.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	47
22.	राजस्थान उच्च न्यायालय	67
23.	गुजरात उच्च न्यायालय	29
24.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	38
25.	केरल उच्च न्यायालय	112
कुल		**2189**

****